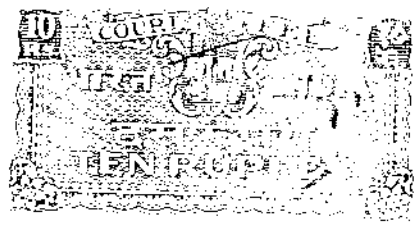
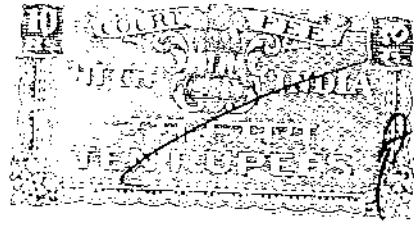


माननीय राजस्व मण्डल मन्त्रीगणालय तर्कित कोर्टरीबा.
 न्यायालय श्रीमान् ~~राजस्व मण्डल मन्त्रीगणालय तर्कित कोर्टरीबा.~~

श्री राजस्व मण्डल मन्त्रीगणालय तर्कित कोर्टरीबा.
 न्यायालय श्रीमान् ~~राजस्व मण्डल मन्त्रीगणालय तर्कित कोर्टरीबा.~~
 27-3-12
 50/3/12



R-936-112

महेश्वर वैश्य तनय स्वामी श्री दशरथ प्रसाद वैश्य उम्र 75 वर्ष वैशाख

कृषि कार्य निवासी ग्राम गदशा तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली

27-3-12

मध्य प्रदेश

निगरानीकर्ता

बनाम

5-4-12

मध्य प्रदेश शासन

निगरानीकर्ता

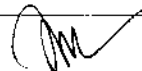
XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 936-एक/12

जिला - सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.6.14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, सिंगरोली के अंतरिम आदेश दिनांक 5.3.12 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा अति. तहसीलदार, सिंगरोली प्रभारी क्षेत्र अमिलिया के राजस्व प्रकरण क्रमांक 11/अ-6-अ/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 3-11-07 के विरुद्ध निगरानी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई । कलेक्टर ने उक्त अपील को आवेदक की अनुपस्थिति तथा आलोच्य आदेश की प्रति पुनरीक्षण के साथ न लगाने के कारण निरस्त किया है । इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।</p> <p>3- आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में सुनवाई दिनांक को 7 दिवस में लिखित तर्क पेश करने हेतु समय चाहा था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।</p> <p>4- अनावेदक शासन पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।</p> <p>5- आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर द्वारा नियत दिनांक को आवेदक के अनुपस्थित रहने तथा आलोच्य आदेश की प्रति निगरानी के साथ न लगाने के कारण प्रकरण को निरस्त किया गया है । संहिता की धारा 48 के अनुसार याचिका के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति</p>	



स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>पेश किया जाना आवश्यक है जब तक कि ऐसी प्रतिलिपि के पेश किए जाने से अभिमुक्ति न दी गई हो । प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि से अभिमुक्ति देने हेतु कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कलेक्टर का जो आदेश है वह वैधानिक दृष्टि से उचित और न्यायिक है होने से पुष्टि योग्य है ।</p> <p>परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है ।</p> <p>उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।</p>	<p>(एम.क. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर</p>